E-mail:-patansamachar@gmail.com
RNI पंजीकरण संख्या HP66824/97
Postal Reg. No. HP/123/SML/2019-22

हिमाचल पाटन समाचार

साप्ताहिक

सबकी सुनें , सबको सुनाए, घर – घर खबर पहुंचाए

हर सोमवार को शिमला से प्रकाशित होने वाला लोकप्रिय समाचार पत्र

वर्ष 25 | अंक 33 | शिमला | 8 – 14 अगस्त 2022 | मूल्य 3.00 रुपये | वार्षिक 200 रुपये

प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों को बहुत लाभ दिए : जयराम

हिमाचल पाटन समाचार , विधानसभा हि.प्र.

हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है और विपक्ष भी इस मामलें को हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच में हर कार्यक्रमों में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर अपने वायदे को दोहरा रही है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक नेता लोगों को आश्वस्त करने में लगे हुए है। कि जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी उसके दस दिनों के भीतर ही प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का तोहफा दिया जाएगा । इसें प्रदेश कांग्रेस अपना सबसे पहला और बड़ा वायदा मान रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन को बताया की प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए कोरोना माहमारी आनें के बावजूद भी उनका वेतन एक भी दिन रोका और कोई पैसा नही काटा गया है जो की अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया की प्रदेश सरकार ने प्रदेश के एमपीएस के कर्मचारियों को बहुत से लाभ दिएं हैं। उन्होने कहा कि प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल करना इतना आसान नही है इसके बावजुद भी प्रदेश सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के हितों की लडाई लडेंगी। वर्तमान सरकार ने सरकार के अशंदान को दिनांक 01–04–2019 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जिससे इन कर्मचारियो को मु0 175 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक लाभ मिल रहा है । इससे राज्य के लाख से अधिक NPS कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान सरकार अशंदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने वाली पहली राज्य सरकार थी। इससे NPS कर्मचारियों की पेंशन मे काफी बढ़ोतरी होगी। इस समय प्रदेश सरकार NPS के अर्न्तगत सरकारी अशंदान पर 911 करोड़ की राशि प्रति वर्ष खर्च कर रही है जबकि वर्ष 2017–2018 के दौरान यह राशि 250 करोड़ की थी।

पिछली सरकार ने Gratuity का लाभ prospective date से दिनांक 22–09–2017 से लागू किया था। इस कारण NPS कर्मचारी जो मई 2003 से सितम्बर 2017 के बीच सेवानिवृत हुइ या जिनकी उस दौरान मृत्यु हुई, वे इस लाभ से वंचित रह गए थे। Covid–19 महामारी के बावजूद वर्तमान सरकार ने इन कर्मचारियों को Gratuity का लाभ देने के लिए आदेश जनवरी 2021 में जारी किये जिससे 5612 NPS कर्मचारियों को 110 करोड़ रुपये का लाभ मिला।

NPS कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान अपंग होने अथवा मृत्यु होने की सूरत मे a Invalid Pension और Family Pension देने के आदेश दिनांक 22–02–2022 को जारी किये गये है। इस निर्णय से दिनांक 15–5–2003 के बाद अब तक सेवाकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुइ अथवा अपंग हुए लगभग 2200 NPS कर्मचारियो के परिवारो को पारिवारिक पेंशन तथा Invalid Pension का लाभ ऐरियर सहित लाभ मिल रहा है इस पर करीब 250 करोड़ रुपये खर्च होगे ।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृति उपदान एवं मृत्यु उपदान (Death& cum& Retirement Gratuity) का लाभ प्रदान किया जा रहा है जिसकी ऊपरी सीमा को दिनांक 1–1–2016 से 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है।

प्रदेश सरकार के भरसक प्रयास के कारण भारत सरकार ने NPS कर्मियो को आयकर मे विभिन्न छुट प्रदान की है जैसे पेंशन को 60 प्रतिशत की अन्तिम निकासी को पूर्णतया कर–मुक्त की दी गई है। पेंशन कोष के 40 प्रतिशत भाग जिसकी Annuity purchase की जाती है को भी पूर्णतया कर मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा सरकारी अशंदान के 4 प्रतिशत को भी कर मुक्त कर दिया गया है।

इसके इलावा NPS कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की तरह Leave Encashment/ GIS/ EÛ&gratia] Medical Reimbursement का लाभ पुरानी पेंशन प्रणाली में आने वाले कर्मचारियों के समान दिया जा रहा है।

जयराम ठाकुर के सामने बौना नजर आया विपक्ष

कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिरा हुई फजीहत

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने प्रदेश सरकार को घेरने के कई प्रयास किए। परन्तू मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के तथ्यों के साथ हाजिर जबाव से उनकी कोशिषे नाकाम रहीं। इस मानसून सत्र विपक्ष ने सबसे बड़े हथियार अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग भी पहली बार किया, जिसके कारण सदन में विपक्ष के बिना तैयारी और बिना तथ्यों के सदन में माहौल खुशनुमा रहा। प्रदेश में चुनावी वर्ष को देखकर विपक्ष ने लोगों के बीच चर्चा का विषय बनने के लिए , सरकार का बढ़ता जनाधार कम करने के लिए कई कोशिषें की। फजीहत तो तब हुई जब इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए विपक्ष के विधायक सही मुददों को सदन में नही उठाकर इधर–उधर की बाते करते रहे। सदन में माहौल खुशनुमा तब हुआ जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी ही फजीहत करवा ली। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समय–समय पर विपक्ष को विभिन्न मुददों पर तथ्यों के साथ आडें हाथों लिया और नसीहत दी कि लोगों के बीच तथ्यों के साथ जाएं अब जनता उनके झांसे और झूठ को जान चुकी है। विपक्ष अपने ही अविश्वास प्रस्ताव से सत्ता पक्ष को घेरने में नाकाम रही। सदन में अपनी गुटबाजी से सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर तंज कसे। मंत्री विकम सिंह ने सुक्खु को मजाकिया अंदाज में कहा की आपने मुख्यंत्री बनना है तो आप चुप बैठिए, इस पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने मंत्री को घेरना शुरू किया तो मंत्री ने तुरंत कहा कि क्षमा चाहता हूं मुकेश जी मैंने तो सुक्खु को मुख्यमंत्री का दावेदार बोल दिया आप ही हो मुख्यमंत्री के दावेदार अब तो चुप हो जाओ। इस बीच पुरे सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों ,अधिकरी दीर्घा,दर्शक दीर्घा, पत्रकार दीर्घा में खूब ठहाके लगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सही मायनों में विप्क्ष खबर में बने रहने के लिए इस प्रस्ताव को लेकर आया है जिसमें वह नाकाम रहे हैं । इसी तरह प्रदेश की जनता भी उन्हे नकार देगी क्योंकि जनता जानती है कि कोविड महामारी के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने ईमानदार प्रयास से प्रदेश का चहुंमुखी विकास किया है और आने वाले समय प्रदेश की जनता भाजपा को भारी जनसमर्थन देगी और यहां पर रिवाज बदलकर भाजपा अपनी सरकार बनाएगी।

लम्पी स्कीन रोग के लिए स्वदेशी वैक्सीन

रोहित पराशर

मानव और जानवर का साथ सदियों से है और सदियों से ही ये दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं। हमारे देा में पशुधन का बहुत महत्व है और अब जब हाल ही में भारत के गोवांशों में गाँठदार त्वचा रोग या लंपी स्किन डिजीज़ के संक्रमण के मामले देखने को मिले हैं। जो की भारत में पहली बार दर्ज किये गये है। भारत जिसके पास दुनिया के सबसे अधिक लगभग 303 मिलियन, मवेशी हैं में बीमारी सिर्फ 16 महीनों के भीतर 15 राज्यों में फैल गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मवेशियों या जंगली भैंसों में यह गाँठदार त्वचा रोग वायरस के संक्रमण के कारण होता है। यह संक्रमित मवेशियों से अन्य स्वाथ्य मवेशियों में फैलता है। देा में तेजी से फैल रहे इस रोग से निपटने के लिए सभी राज्यों में पाु चिकित्सक डटे हुए हैं, और ऐसे समय में देश के पशुधन के लिए बड़ी राहत प्रदान करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुओं को लम्पी स्किन रोग से बचाव के लिए बुधवार को स्वदेशी वैक्सीन (लम्पी–प्रो वैक–इंड/) लॉन्च की। यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, हिसार (हरियाणा) ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (बरेली) के सहयोग से बनाई है। तोमर ने इस वैक्सीन को लम्पी बीमारी के निदान के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि मानव संसाधन के साथ ही पशुधन हमारे देश की बड़ी ताकत है, जिन्हें बचाना हमारा बड़ा दायित्व है.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत यह वैक्सीन विकसित करके एक और नया आयाम स्थापित किया गया है। अश्व अनुसंधान केंद्र व पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के प्रयासों ने लम्पी रोग के टीके को विकसित करके देा ही नहीं दुनिया भर में फैले इस रोग के उपचार के लिए एक नई दिाा दिखाई है।

इस वैक्सीन को तैयार करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल लम्पी रोग राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में फैली हुई है. वैज्ञानिकों ने लम्पी रोग की चुनौती को स्वीकार किया और कम समय में सीमित परीक्षण में सभी मानक स्तर पर शत–प्रतिशत कारगर वैक्सीन विकसित की है। जो लम्पी बीमारी से निजात दिलाने में असरकारी होगी। अब पाुओं को राहत के लिए यह वैक्सीन जल्द से जल्द बड़ी तादाद में मुहैया कराई जाएगी। देश में तीस करोड़ पशुधन हैं, मूक पशुओं की तकलीफ समझकर उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र राहत देने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। लंपी स्किन डिजीज का प्रकोप हिमाचल में भी दिखने लगा है। पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकारी आंकडों के मुताबिक अभी तक 1000 जानवर इस बीमारी से पशु प्रभावित हो चुके हैं। लंपी स्किन डिजीज के पहले मामले की पुष्टी 26 जुलाई को शिमला के चायली में हुई थी और अभी तक इस बीमारी की वजह से 58 गायों की जान जा चुकी है।

लंपी स्किन डिजीज से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले सिरमौरए सोलन और उना जिला है। उना जिला में लंपी स्किन डिजीज के 230 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से 4 पशुओं की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर मामले पंजाब के साथ सटे गगरेट क्षेत्र से हैं। इसके अलावा उना ब्लॉक में भी ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दी गई हैं। वहीं हरियाणा के साथ बार्डर साझा करने वाले सिरमौर क्षेत्र में भी लंपी स्किन डिजीज के कई मामले देखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में यह बीमारी गायों में देखी गई है और पशु गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में गायों की संख्या 28 लाख के करीब है। पीएचडी इन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी डॉ सुशील सूद का कहना है कि जिन पशुओं को वैक्सीन नहीं लगी है वह ज्यादा संवेदनशील हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की ऐसी धारणा है कि वैक्सीन लगाने से जानवर दूध कम देता है जिसके चलते लोग वैक्सीनेशन कम करवाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कुछ दिनों के बाद जानवर उतना ही दूध देना शुरू कर देता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि लम्पी स्किन डिजीज जूनोटिक है और इसके मनुष्यों में भी फैलने का भय है हालांकि ऐसा मामला अभी तक सामने नहीं आया है फिर भी इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि यह मच्छरों, मक्खियों और जूँ के साथ पशुओं की लार तथा दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से फैलता है।

पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ अविनाश का कहना है कि लंपी स्कीन रोग के पहले मामले की पुष्टि के बाद ही विभाग ने एहतियातन पूरे विभाग के कर्मचारियों को सतर्क कर दिया था और अभी जिन जिन क्षेत्रों में इस रोग के मामले देखने को मिले हैं वहां पर वैक्सीनेान का काम जोरों पर किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग घरेलू इलाज न करें और यदि पशुओं में लम्पी स्किन डिजीज के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो पशु चिकित्सकों के पास जाएं। वहीं महामारी विज्ञान के उप निदेशक डॉ अरूण सरकैक का कहना है कि प्रदेश लंपी स्किन डिजीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेपीड एक्शन टीमों का गठन किया गया है। जिन क्षेत्रों में इस बीमारी के मामले देखे गए हैं वहां के 5 किलोमिटर के दायरे में वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। इसके अलावा उस क्षेत्र को संवेदनशिल घोषित किया गया है।

लंपी स्कीन रोग के लक्षण

यह पूरे शरीर में विशेष रूप से सिर, गर्दन, अंगों, थन, मादा मवेशी की स्तन ग्रंथि और जननांगों के आसपास दो से पाँच सेंटीमीटर व्यास की गाँठ के रूप में प्रकट होता है। यह गाँठ बाद में धीरे.धीरे एक बड़े और गहरे घाव का रूप ले लेती है।इसके अन्य लक्षणों में सामान्य अस्वस्थता आँख और नाक से पानी आना बुखार तथा दूध के उत्पादन में अचानक कमी आदि शामिल है। इसके अलावा पशु की खाने की क्षमता भी कम हो जाती है।

स्कीन रोग की रोकथाम

गाँठदार त्वचा रोग का नियंत्रण और रोकथाम चार रणनीतियों पर निर्भर करता है जो निम्नलिखित हैं .

आवाजाही पर नियंत्रण :– क्वारंटीन, टीकाकरण, संक्रमित पशुओं का प्रबंधन। इस वायरस के लिए टीकाकरण ही रोकथाम व नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन है। यदि लक्षण दिखाई दे तो त्वचा में द्वितीयक संक्रमणों का उपचार गैर. स्टेरॉयडल एंटी .इंफ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक दवाओं के साथ किया जा सकता है गौर रहे कि हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी राज्य है और यहां साढे नौ लाख किसान बागवान प्रदेश की जीडीपी में 13 फीसदी का योगादान देते हैं। ऐसे में खेती और बागवानी की रीढ़ गाय है और गायों में फैले इस रोग से यहां के किसान बागवान चिंतित है। इसलिए किसान–बागवानों ने सरकार से इस बीमारी पर शीघ्र रोकथाम के लिए प्रभाव कदम उठाने की गुहार लगाई है साथ ही सभी जानवरों की वैक्सीनेशन की भी अपील की है। इसके अलावा स्वदेी वैक्सीन के आने से पाुधन पालकों को एक आशा की किरण नजर आई है और पशुधन पालकों ने इस वैक्सीन का जल्द गांव स्तर तक पहुंचाने की मांग की है।

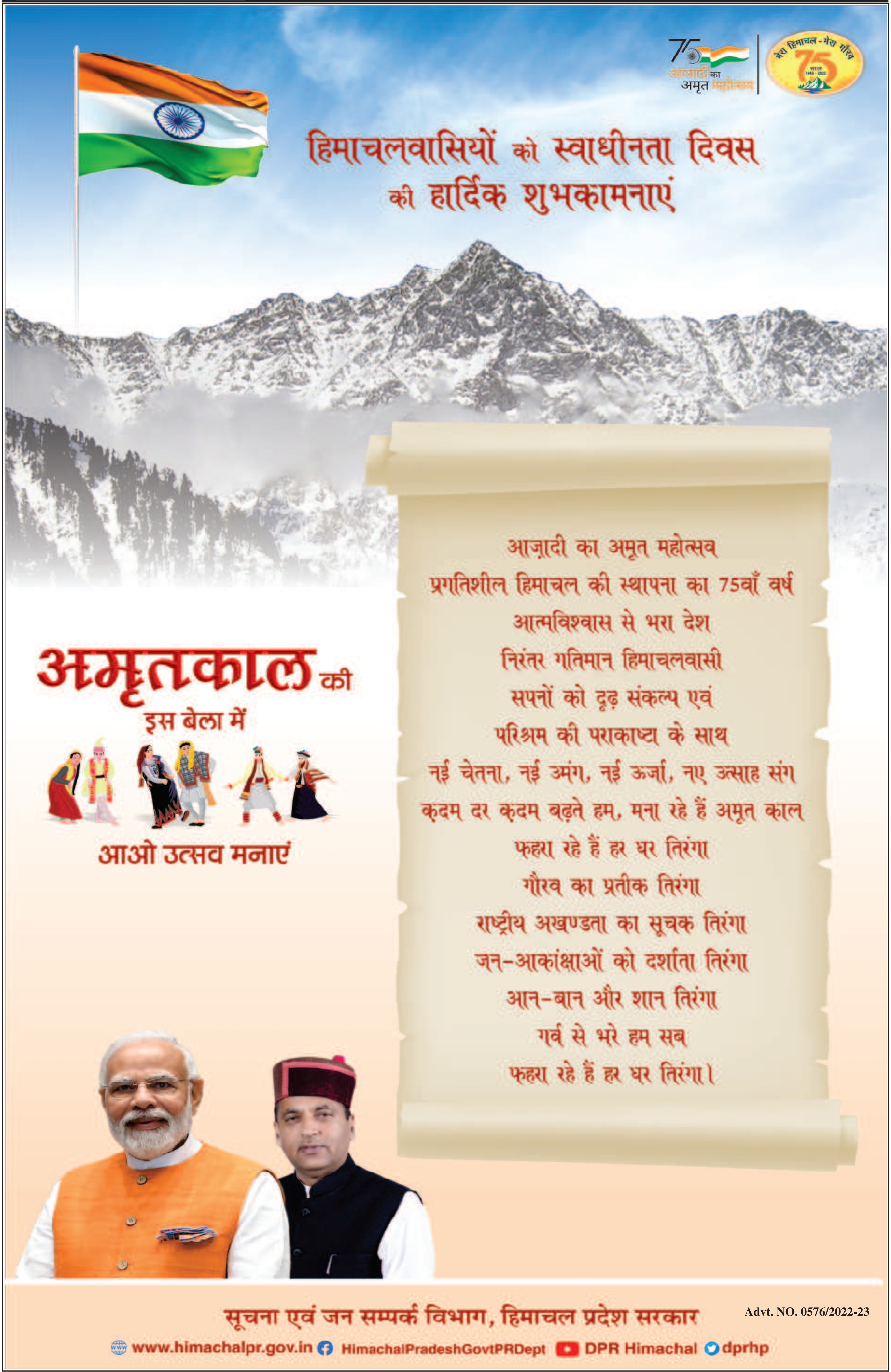
हिमाचलवासियों को स्वाधीनता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
आज़ादी का अमृत महोत्सव
प्रगतिशील हिमाचल की स्थापना का 75वाँ वर्ष
आत्मविश्वास से भरा देश
निरंतर गतिमान हिमाचलवासी
सपनों को दृढ़ संकल्प एवं
परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ
नई चेतना, नई उमंग, नई ऊर्जा, नए उत्साह संग
कदम दर कदम बढ़ते हम, मना रहे हैं अमृत काल
फहरा रहे हैं हर घर तिरंगा
गौरव का प्रतीक तिरंगा
राष्ट्रीय अखण्डता का सूचक तिरंगा
जन-आकांक्षाओं को दर्शाता तिरंगा
आन-बान और शान तिरंगा
गर्व से भरे हम सब
फहरा रहे हैं हर घर तिरंगा।
अमृतकाल की
इस बेला में
आओ उत्सव मनाएं
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
Advt. NO. 0576/2022-23
www.himachalpr.gov.in HimachalPradeshGovtPRDept DPR Himachal dprhp

प्राकृतिक खेती :

सेब बागवानों के खिलते चेहरे

कृषि विज्ञान केन्द्र शिमला में प्राकृतिक खेती से सेब पर बागवानों को किया जागरूक ,किसान मेले का आयोजन

शिमला, हिमाचल पाटन समाचार रोहडू स्थित कृषि विज्ञान केंद्र शिमला में सेब में प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले का आयोजन प्राकृतिक कृषि खुशहाल किसान योजना के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने प्राकृतिक खेती पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्राकृतिक खेती से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न किसान संस्थाओं के सदस्यों ने केवीके में प्रदर्शनी में भाग लिया। विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ दिवेन्द्र गुप्ता ने स्वागत सम्बोधन प्रस्तुत किया। सभा को संबोधित करते हुए डॉ. राम कृष्ण शर्मा, परियोजना निदेशक आत्मा शिमला ने जिले में प्राकृतिक खेती के तहत की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। डॉ. एन एस कैथ, प्रधान वैज्ञानिक और केवीके शिमला के प्रभारी ने सेब में प्राकृतिक खेती के संभावनाएं और इसका उपयोग कृषि आय बढ़ाने के लिए कैसे किया जा सकता है, के बारे में बताया।

कृषि में महिलाओं और किसी भी नई सरकारी योजनाओं की सफलता में महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए प्रोफेसर चंदेल ने कहा कि यह नई कृषि प्रणाली केवल तभी अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर सकती है जब महिलाएं इसके कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाएं। स्थानीय बीजों और उसके लाभों के महत्व पर प्रोफेसर चंदेल ने कहा कि किसानों से अपने स्थानीय बीजों और फसलों को संरक्षित करने का आग्रह किया, जिनकी खेती पिछले कुछ दशकों में काफी कम हो गई है। उन्होंने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से पारंपरिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने में मदद करने का आग्रह किया।

प्रोफेसर चंदेल ने कहा कि सेब की खेती की लागत, जो कि राज्य की एक प्रमुख नकदी फसल है, प्राकृतिक खेती को अपनाने से काफी कम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल उपज की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और कृषि के लिए पानी के उपयोग में कमी करके पर्यावरण संरक्षण में मददगार है। इस अवसर पर प्राकृतिक खेती कर रहे कई किसानों ने अपने बगीचे में इस तकनीक को अपनाने के अपने अनुभव साझा किए। प्राकृतिक खेती में लगे किसान समूहों को भी सम्मानित किया गया। डॉ. जेसी भारद्वाज, केवीके शिमला के पूर्व प्रभारी, डॉ. कुशल मेहता, एचडीओय डॉ. इबजनाई कुर्बाह, किसान मेले में कई किसान संस्थाओं के प्रतिनिधि और बागवानी और कृषि विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। किसान मेला के बाद रोहडू ब्लॉक के गावना गांव में प्रगतिशील किसान संजीव झामटा के बगीचे का दौरा किया। उन्होंने उच्च धनत्व वाले वृक्षारोपण के तहत 4000 से अधिक सेब के पौधे लगाए हैं एक ब्लॉक को प्राकृतिक खेती में भी बदल दिया है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन की अन्तिम तिथि 31 अक्तूबर

शिमला,हिमाचल पाटन समाचार

शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल खोल दिया है। उन्होंने कहा कि पात्र विद्यार्थी इन योजनाओं के तहत www.scholarship.gov.in पर या www.minorityffaairs.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से या मोबाइल ऐप-नेशनल स्कॉलरशिप्स (एनएसपी) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन योजनाओं के तहत भारत में सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय, संस्थान, महाविद्यालय और विद्यालय में अध्ययनरत केन्द्र से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक वर्गों बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, सिक्ख और पारसी के आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नए और नवीनीकरण दोनों प्रकार के आवेदनों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि एनएसपी पहले ही 20 जुलाई, 2022 को खोला जा चुका है और इसके अन्तर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2022 है। आईएनओ स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2022 और दूसरे स्तर के सत्यापन की तिथि 30 नवंबर, 2022 निर्धारित की गई है।

पाटन समाचार
संस्थापक :
ब्रहमलीन श्री नीलकमल ठाकुर जी

सम्पादकीय..........

सड़कों के विकास से हिमाचल में महकता जीवन

अधोसंरचना विकास राज्य में विकास की गति प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है और सड़क अधोसंरचना को विकसित करने से विकास पर कई गुणा प्रभाव पड़ता है। रेल व हवाई यातायात के सीमित साधनों के कारण हिमाचल में सड़कों का महत्व और भी बढ़ जाता है, इसलिए राज्य सरकार हिमाचल में सड़क सम्पर्क को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दे रही है।

हिमाचल प्रदेश में कुल 40,020 किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं व राज्य सरकार द्वारा 10591 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है तथा 2278 पुल निर्मित किए गए हैं। राज्य सरकार ने केवल चार वर्षों की अवधि में हिमाचल प्रदेश में 3527 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कें, 268 किलोमीटर जीप योग्य सड़कें और 268 पुलों का निर्माण किया हैं

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया है और नवनिर्मित पंचायतों में सड़क सम्पर्क प्रदान करने के उद्देश्य से हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायतों के पुनर्गठन से ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 3615 हो गई है, इनमें से 3556 पंचायतें सड़क से जुड़ी हैं व शेष 59 पंचायतों में से 20 पंचायतों को 2022–23 में सड़क से जोड़ा जाएगा। वर्ष 2019 से दिसम्बर, 2021 तक 219 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया जिनकी आबादी 1500 से अधिक है, 1000 से 1499 की आबादी वाले 296 गांवों, 500 से 999 की आबादी वाले 1324 गांवों, 250 से 499 की आबादी वाले 3655 गांवों तथा 250 से कम आबादी वाले 5097 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है।

वर्तमान में 19 राष्ट्रीय उच्च मार्ग, जिनकी कुल लम्बाई 2592 किलोमीटर है, राज्य सड़क नेटवर्क की मुख्य जीवन रेखा है, जिनमें से 1238 किलोमीटर सड़कों का रख–रखाव और विकास हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 865 कार्य पूर्ण किए जा चुके है और 5408 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है। राज्य में ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि–नाबार्ड के तहत 68 पुल तथा 498 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि के तहत राज्य में 28 पुल निर्मित किए गए हैं तथा 65.8 किलोमीटर लम्बी सड़कों का उन्नयन किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया है। वर्ष 2020 में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मण्डी जिले को 30 जिलों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जबकि हिमाचल प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। जिला मण्डी ने 2020–21 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सबसे अधिक लम्बाई के सड़क निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। राज्य के अन्य सात जिलों जैसे सोलन, चम्बा, शिमला, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर और हमीरपुर ने भी देश के सर्वश्रेष्ठ 30 जिलों में अपना स्थान बनाया। हिमाचल प्रदेश में पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के तहत 23 अक्तूबर, 2020 तक 1104 किलोमीटर सड़क निर्माण कर बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

शिमला, हिमाचल पाटन समाचार

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में 76 मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर–प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने को मंजूरी प्रदान की गई। इन वेलनेस सेंटरों के लिए स्टाफ नर्सों के 152 पदों और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 76 पदों को सृजित कर अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने किन्नौर जिला की पूह तहसील में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए रिपलो में पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में बिलासपुर जिला की सदर तहसील के शिकरोहा में पटवार वृत्त सृजित करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में मण्डी जिला की चच्योट तहसील के अंतर्गत केलोधार में कानूनगो वृत्त सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा में लोक निर्माण विभाग के दो नये अनुभाग (सिविल एवं विद्युत) सृजित करने एवं इनमें आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।

बैठक में राज्य निर्वाचन विभाग में निर्वाचन कानूनगो के दस पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भाली तथा सोलधा में विज्ञान की कक्षाएं (नॉन मेडिकल) आरम्भ करने तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अमनी तथा त्रिलोकपुर में वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने और विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के मनाली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोशाल, जगतसुख और नाथन में वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने और प्रवक्ताओं के सात पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में ऊना जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कध में वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने और तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में कुल्लू जिला के नागरिक अस्पताल बंजार को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ–साथ इस अस्पताल के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 35 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में मण्डी जिला में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र पुराना बाजार तहसील सुन्दरनगर को 10 बिस्तर क्षमता के आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ–साथ विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के तहत खिलाड़ियों को प्रदान किए जाने वाले दैनिक भत्ते को राज्य के भीतर वर्तमान में दिए जाने वाले 120 रुपये से बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी और राज्य के बाहर 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी करने का निर्णय लिया।

बैठक में कांगड़ा जिला के प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड पालमपुर, नगरोटा बगवां और भवारना को विभाजित कर क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए धीरा में नया प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड खोलने को अनुमति प्रदान की गई।

बैठक में कांगड़ा जिला के डाडासिबा में नया विकास खण्ड कार्यालय खोलने के साथ–साथ विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के पट्टा में नया विकास खण्ड कार्यालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मानसून सत्र में सदन को संबोधित कर

भावुक हुए विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार

हिमाचल पाटन समाचार , विस हिमाचल प्रदेश की तेहरवीं विधान सभा का पंद्रहवां सत्र जोकि मानसून सत्र के समापन पर सदन को संबोधित करते हुए प्रदेश विधनसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार भावुक हो गए। स्व. नरेन्द्र बरागटा को याद करते हुए उन्होने कहा कि बरागटा ही उन्हे इस आसन तक लेकर आए थे। उस समय को याद करते हुए उन्होने कहा कभी नही सोचा था की इस आसन में सदन का अच्छी तरह से चला सकूंगा, मन में सोचता रहता था क्या में इस सदन की कार्यावाही का निष्पक्ष चला सकूंगा जो कि बहुत ही मुश्किल समय था मेरे लिए परन्तु आप सभी सदन के माननीयों के सहयोंग के कारण ही मैं यह कार्य पूर्ण कर पाया हूं। उन्होने कहा कि यह मानसून सत्र 10 अगस्त, 2022 से आरम्भ हुआ तथा इस मानसून सत्र के दौरान कुल 04 बैठकें आयोजित की गई। इस माननीय सदन की कार्यवाही 22 घंटे 40 मिनट चली। पिछले पांच वर्षों में अभी तक तेरहवीं विधान सभा की कुल 140 बैठकें आयोजित की गई हैं जो इस बात का परिचायक है कि माननीय सदस्य लोकतान्त्रिक प्रणाली में अटूट विश्वास रखते है तथा हिमाचल प्रदेश विधान सभा की उच्च परंपराओं तथा गरिमा का बेहद सम्मान करते हैं । मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि कोविड़ –19 की बजह से वर्ष 2020 का शीतकालीन सत्र हमें स्थगित करना पड़ा था बावजूद इसके हम 140 बैठकें आयोजित करने में कामयाब हुए है जिसका श्रेय हिमाचल प्रदेश सरकार के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों तथा विशेष रूप से विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को जाता है जो सीधे तौर पर इसके आयोजन से जुड़े हैं। इन 5 वर्षों में कुल 10513 सूचनायें प्रश्नों के रूप में माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई है जिनमें से 7414 तारांकित तथा 3099 अतारांकित प्रश्न प्राप्त हुए जिन्हें आगामी कार्यवाही हेतु सरकार को प्रेषित किया गया। इन 5 वर्षों में कुल 77 सरकारी विधेयक पूरस्थापित किये गये तथा जिनमें से 69 का पारण किया गया। इन पांच वर्षों में सभा की समितियों द्वारा कुल 683 प्रतिवेदन सभा में स्थापित किये गये। अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया था हमारा देश व प्रदेश भी उसमें शामिल था। बेहद संकटपूर्ण समय के बावजूद भी हमने एक शीतकालीन सत्र को छोड़कर सभी सत्र आयोजित किये। प्रश्न भी हुए, चर्चा भी हुई, बिलों का पारण भी हुआ लेकिन कोविड़ –19 के लिए तय नियमों व शर्तों का अक्षरू–रक्षरू पालन किया गया। हर तरह की सावधानी बरती गई, सारी व्यवस्थायें कोरोना PROTO COL के हिसाब से सुनिश्चित की गई जहां विधान सभा परिसर में प्रवेश पाने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ा वहीं कोरोना टेस्ट के लिए डॉक्टर व पैरा मैडिकल स्टॉफ की टीम तैनात रही, आइसोलेशन वार्ड स्थापित किया गया, ऐम्बुलैंस की व्यवस्था परिसर में की गई तथा विधान सभा सचिवालय परिसर, सदन तथा मुख्य द्वारों को पूरी तरह से सैनिटाईज किया गया ताकि Zero Error का भी सन्देह न रहे। इसके अलावा विधायकों की सीटों को पोलिकार्बोनेट शीटस से पृथक किया गया तथा सभी को फेस मास्क तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। मैं सदन के नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को बधाई भी देना चाहता हूं तथा धन्यवाद भी करता हूं कि उनके कदम इस भीषण महामारी से

डगमगाये नहीं, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ इस विनाशकारी महामारी का सामना करने के लिए उच्च प्रशासनिक व बेहतरीन स्वास्थ्य ढाचे को मजबूत किया तथा समय –समय पर डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा अन्य Front Line Worker की उन्होंने हौसला बजाही की तथा उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश जनमानस के जीवन को बचाने वाले टीकाकरण में पूरे देश में अब्बल रहा। इन पांच वर्षों में हिमाचल प्रदेश विधान सभा कई कार्यक्रमों के आयोजन की गवाह बनी। वर्ष 2018 में विधान सभा में राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलन जोन–IV का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोक सभा की तत्कालीन माननीय अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन जी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। सितम्बर, 2021 में हिमाचल प्रदेश राज्य स्वर्णिम वर्ष के सुअवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने इस माननीय सदन को सम्बोधित किया था। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं 100 वर्ष पूर्व सितम्बर, 1921 को शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। मुझे यह बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि उसी सम्मेलन का सहस्त्राब्धि समारोह आयोजित करने का इस विधान सभा को अवसर प्राप्त हुआ तथा इसका आयोजन 16 से 19 नवम्बर , 2021 तक किया गया जिसमें 23 राज्यों की विधान परिषदों तथा विधान सभाओं के पीठासीन अधिकारी शामिल हुए तथा विशेष तौर पर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के चेयरमैन एवं लोक सभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी स्वंय इस सदन में उपस्थित थे व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेद्र दामोदर दास मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन को सम्बोधित किया था तथा राज्य सभा के उप–सभापति श्री हरिवंश जी तथा केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री का भरपूर सहयोग व मार्गदर्शन मिला।सत्र के दौरान मेरा भरसक प्रयास रहा कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले। माननीय संसदीय कार्यमन्त्री, मुख्य सचेतक तथा उप मुख्य सचेतक का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सदन में दोनों पक्षों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखा। मैं अपने सहयोगी माननीय उपाध्यक्ष, विधान सभा व सभापति तालिका के सदस्यों का जिन्होंने कार्यवाही के संचालन में बहुमूल्य सहयोग दिया का भी धन्यवाद करता हूं। मैं सदन के समस्त सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस सदन की समय सीमाओं और नियमों का पालन करते हुए अपने–अपने विषयों को सदन में उठाया तथा इस विधान सभा की ऐतिहासिक उच्च परम्पराओं तथा गरिमा को बनाये रखने में अपना बहुमुल्य योगदान दिया जिसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। मैं विधान सभा सचिव और समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग के लिए उनका आभार करता हूं जिन्होंने विषम परिस्थितियों के बावजूद इस सत्र के लिए दिन–रात कार्यकर इस सत्र से सम्बन्धित कार्य को समयवद्ध तरीके से निपटाने में पूर्ण सहयोग दिया। मैं पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सभी के लिए पौष्टिक तथा स्वादिष्ट भोजन की समय–समय पर समुचित व्यवस्था की।मैं आप सभी प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं आप सभी ने विधान सभा की कार्यवाही को प्रदेश के जन–जन तक पंहुचाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।हम इस वर्ष ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मना रहे हैं। परसों स्वतन्त्रता दिवस है इसकी मैं आप सभी को तथा प्रदेश वासियों को अग्रिम बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सभी प्रदेशवासी अपने–अपने घरों में तिरंगा फहराकर इस महोत्सव को यादगार, चिरंजिवी व अविस्मरणीय बनायेंगे। आज वर्तमान सरकार के आखिरी सत्र का आखिरी दिन था जिसका समापन हो चुका है। मैं सभी माननीय सदस्यों को आने वाले समय के लिए अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनायें देता हूं। आपसे मुलाकात करने का सदैव अभिलाषी रहूंगा।

(संस्थापक संपादक स्व.श्री नील कमल ठाकुर), स्वामी ,प्रकाशक, मुद्रक संजय ठाकुर द्वारा टूटू शिमला-11 फोन : 98052-26033,98050-27601, से प्रकाशित व सिगमा प्रिंटर्ज कसुंपटी, शिमला से मुद्रित। संपादक संजय ठाकुर
मान्दः-प्रबंधक संपादक मार्शल ठाकुर। समाचार पत्र में सभी खबरों को पारदर्शिता के साथ पढ़ा व कम्पोज किया जाता है इसके बावजूद अगर छपाई व कम्पोजिंग में गलती रहे तो उसका जिम्मेवार हिमाचल पाटन समाचार पत्र समूह नही होगा। हिमाचल पाटन समाचार से संबंधित विवादों का निपटारा शिमला न्यायालय में होगा।